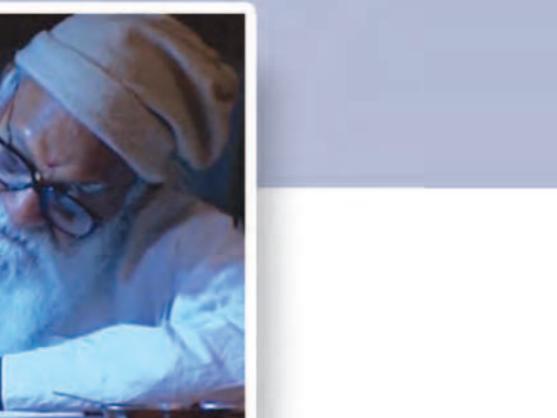


नानाजी की पाती युवाओं के नाम



व प्रधानमंत्री पर खर्च की गई धनराशि 122.52 करोड़ रुपये थी, जो लोकसभा के कूल खर्च का आधा और राज्य सभा पर खर्च होने वाली राशि से 30.39 करोड़ रुपये ज्यादा था। इस पर यदि एसपीजी (विशेष सुक्ष्म समूह) पर होने वाले 79.46 करोड़ रुपये के खर्च को भी जोड़ जाए तो यह लोकतंत्र हमारी मन्त्रिपरिषद, संसद और राष्ट्रपति कार्यालय को बेहद खर्चीले लोक संस्थान बना देता है।

परंतु निश्चय ही मैं अपनी बात को निराश का छहता। अतः उनके व्यक्तिगत वेतन व सुविधाओं पर कुछ नहीं कहूँगा परंतु मैं इस बात पर दुःखद आश्चर्य जरूर प्रकट करनगा कि जब देश में एक और कठोरों लोग विज्ञानियों की छत के ज़ीरों को मजबूर हैं, ऐसे में राजप्रासादबृंग राष्ट्रपति भवन के राजराजाव पर इतना धन खर्च किया जाए। मैं इसमें कोई औचित्य नहीं देखता कि इनके लिए एक व्यक्तिगत या परिवार को 350 करोड़ रुपये बाला घर दिया जाए।

उपरोक्त तथ्यों व स्थितियों ने लोगों के मन में संसद के प्रति सम्मान को कम करने में अपना योगदान दिया है। इस संदर्भ में इस बात पर भी जोर देना होगा कि संसद की व्यवस्था का निर्धारण करने वाले संविधान के बन्दुच्छेद 79 से 123, जिसमें संसद का विशेषाधिकार भी शामिल है, ऐसी किसी व्यवस्था की बात नहीं करते जो इसके नियंत्रण व संतुलन की भीतर की बजाए बाहर से संचालित कर सके। दृष्ट्य है कि अभी यह काम होना चाही है, अतः इस दिशा में एहता कदम उठाने की जरूरत है। इसमें सांसदों को केवल लाभ उठाने वाला बनाने से रोकने के लिए एक आग बहस शुरू करने की जरूरत है। साथ ही इनके वेतन व भत्तों के संबंध में पड़ताल करने की भी आवश्यकता है। ताकि लोगों की ज़रूरों में संसद की खोई गिरावट व प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया जा सके।

मेरी यह स्पष्ट धारणा है कि यदि इस तरह की

दखलदाजी पर रोक नहीं लगाई गई तो यह लोकतंत्र की चूले हिता देगा और जनता के मन में इसके प्रति असंत्ता कम करेगा। अतः आप सभी बुद्धिजीवियों एवं विचारनायकों से मेरी विवरण प्रार्थना है कि इस विषय पर गवर्नर्स को सोचें और इस मुद्दे को उचित गंभ पर उदायां ताकि इस संबंध में एक विशिष्ट पंचांग और संस्थानिक तंत्र स्थापित किया जा सके, जो वैद्यानिक हो।

परंतु निश्चय ही मैं अपनी बात को निराश का बिल्ड पर खल नहीं करना चाहता। दीनदयाल शोध संस्थान ने एक ऐसा मॉडल विकसित किया है जिसमें आम लोगों की पहल और उनके पुरुषार्थ को बढ़ावा दिया जाता है। इसी भावना और उत्साह को लेकर यह संभव हुआ है कि आज चित्रकूट के आस-पास के 80 गांवों में-

- शून्य वेरोजगारी
 - शून्य गरीबी
 - शून्य कुपोषण
 - शून्य मुकदमेवाली
 - और साफ-सुधरे व हरे-भरे गांवों
- के सपने को सच कर दिखाया है। वह भी नियार्थीत समय सीमा से पूर्व।

पुरानी पीढ़ी के कई उघोरपतियों को याद होगा कि सन् 1977 में सक्रिय राजनीति से सन्वास लेते समय मैंने उनसे सामुदायिक विकास के कारों में सक्रिय भागीदारी देने का आग्रह किया था। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि देश के उघोरपतियों में विलक्षण प्रबंधकीय प्रतिभा और क्षमताएं हैं।

औरोपीयक घरानों की उत्तरोत्तर प्रगति में उनके ये बुण्ड परिलक्षित भी होते हैं। लोकिन सामाजिक व

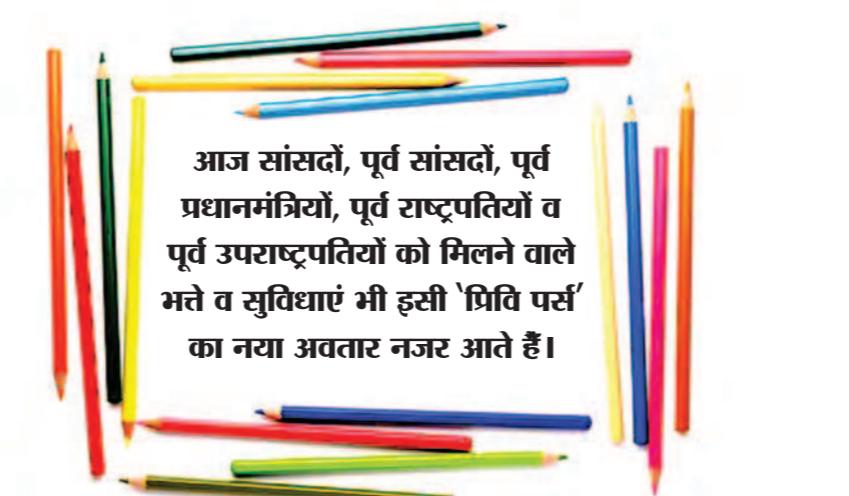
संस्थानिक गतिविधियों में उनका इत्तेमात नहीं हो रहा है। 1977 में मैंने जब फिरकी के तत्कालीन शश्वत श्री हरिशंकर सिंघानिया से अपने संगठन के माध्यम से उघोरपतियों को सामुदायिक विकास गतिविधियों के लिए प्रेरित और संगठित करने का निर्देश किया था। उसके परिणामस्वरूप कई उघोर, पर्याप्त अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं व प्रयासों के साथ इसके लिए आगे भी आए थे। परंतु दुर्भाग्य से यह प्रयास एक सामृद्धिक गति नहीं प्राप्त कर पाया। मैं एक बार पुनः सभी औरोपीयक व व्यापारिक संगठनों का आहान करता हूँ कि वे आगे आए और विकास के इस महायज्ञ में योगदान देने के लिए अपने सदस्यों को प्रेरित करें।

शुभाकांक्षी

नाना देशमुख

(नाना देशमुख)

आज सांसदों, पूर्व सांसदों, पूर्व प्रधानमंत्रियों, पूर्व राष्ट्रपतियों व पूर्व उपराष्ट्रपतियों को मिलने वाले भरे व सुविधाएं भी हीसी 'प्रियि पर्स' का नया अवतार नजर आते हैं।



नाना देशमुख
(नाना देशमुख)